

SHRI F. A. AHMED : So far as protein manufacture is concerned, it is supposed to be manufactured out of vegetarian things like soya bean and many other oil seeds.

MR. SPEAKER : The Minister assures that it is all vegetarian.

SHRI AMRIT NAHATA : Does the hon. Minister know that there is a part in our country known as the Thar desert in the north-western Rajasthan where milk is cheaper than water, but since the area is cut off from the rest of the country, would the Minister consider setting up a modern dairy there to produce baby foods and milk products so that they can be supplied to the rest of the country ?

SHRI F. A. AHMED : I will forward the suggestion of the hon. Member to the Food Minister.

श्री राम चरण : हमारा शहर खुर्जा सारे हिन्दुस्तान में हमेशा घी के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन जब से केन्द्रीय सरकार ने हमारे क्षेत्र में ग्लैक्सो लैबोरेटरीज नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को बेबी फूड और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने का प्लांट लगाने दिया है, तब से हम अनाथ जैसे हो गये हैं और हमें शुद्ध दूध तथा घी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का सारा दूध उस कम्पनी के यहां चला जाता है। क्या सरकार ऐसी प्राइवेट कम्पनीज को हमारे क्षेत्र में प्लांट बनाने और दूध इकट्ठा करने से रोकेंगी, जिससे वहां के लोगों को शुद्ध दूध और घी उपलब्ध हो सके ?

श्री कृष्णरहीन अली अहमद : एक तरफ तो यह मांग की जा रही है कि इस किस्म के फूड की प्रोडक्शन में इजाफा किया जाये और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो इस किस्म की दूध की प्रोडक्ट्स को तैयार कर रहे हैं, उनको रोक दिया जाये।

COMPANIES' CONTRIBUTIONS TO POLITICAL PARTIES

+

*845. **SHRI YAJNA DATT SHARMA :**
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the different Ministries of the Government of India who were examining the proposal to stop completely the companies' contributions to political parties have finalised their proposals;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATH REDDI) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

श्री यज्ञदत्त शर्मा : मंत्री महोदय जानते हैं कि समवायों के द्वारा राजनीतिक दलों को, और खासतौर से शासक दल को, अंशदान दिये जाने के कारण शासन की आर्थिक नीतियां प्रभावित होती हैं और उसके कारण हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में एकाधिकार के निहित स्वार्थ तथा आर्थिक विषमतायें आदि कई समस्यायें पैदा होती हैं। क्या सरकार तत्काल कोई इस प्रकार की नीति अपनाने या कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है, जिससे कोटा और परमिट आदि के सम्बन्ध में जो अनियमिततायें और पक्षपात चल रही हैं, उनको तत्काल रोका जा सके ?

SHRI RAGHUNATH REDDI : Sir, this question arose on the floor of this House as well as the other House several times. In fact hon. Shri Madhu Limaye had moved a Bill and during the course of discussion Government had given him an undertaking that after examining the various aspects of this question a Bill will be introduced in order to achieve the purpose of banning contributions to political parties by companies. The only thing which has delayed the introduction of the Bill during the current session is this. It is not merely a question of the companies registered under the Companies Act which will have to be taken into account but also of private firms, partnerships and trusts which are not covered by the company law. Therefore, to achieve the very purpose which the hon. Member has mentioned, namely to prevent the corruption of public life by the inroads made by the private moneys, the form in which the legislation will have to be brought

in will have to be considered. We shall have to study the various laws that have already been passed and by combining and evaluating the entire thing we shall have to prepare a Bill and introduce it.

श्री यशवन्त शर्मा : जहां तक अध्ययन करने का सवाल है बहुत पहले पूज्य महात्मा गांधी से लूई फिशर ने यह प्रश्न किया था कि शासन की नीतियों के कारण आर्थिक स्थिति हमारी प्रभावित होती है, आप इसको रोकने के लिए क्या करेंगे या क्या कर रहे हैं ? तो महात्मा जी ने भी आश्वासन दिया था कि हमें इस प्रश्न पर विचार कर के, अध्ययन कर के निश्चित रूप से कोई रास्ता निकालना होगा। तो मेरा यह कहना है कि मेरे प्रश्न का उत्तर तो बिलकुल अस्पष्ट और बेग है। दूसरा प्रश्न मैं करना चाहता हूँ कि क्या इस कंपनी विधेयक के अन्दर आप बहुत जल्दी राजनैतिक दलों को रुपया देने के ऊपर कानूनी पाबन्दी लगाने के लिए तैयार हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री कृष्णचंद्रिनी अली अहमद) : यह तो कहा गया है। इस वक्त जितनी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वह पोलिटिकल पार्टियों को रुपया देती हैं। उस रोज मैंने यही अश्वोरोस हाउस को दिया था कि हम आइन्दा सेशन में एक बिल लायेंगे जिसके जरिए से कंपनियों को किस तरह से पोलिटिकल पार्टियों को फंड देने से रोका जाय उसकी व्यवस्था की जायगी।

श्री रवि शर्मा : आज चूंकि चीनी का 40 प्रतिशत मुक्त व्यापार चीनी के व्यापारियों को दे दिया गया है उसके बारे में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि चीनी के मिल मालिकों ने कांग्रेस दल को बहुत सा राजनैतिक चन्दा दिया जिसके कारण इस तरह 40 प्रतिशत चीनी खुले बाजार में बेचने की छूट उनको दी गई ?

श्री कृष्णचंद्रिनी अली अहमद : जो जो रुपया मिलों ने पोलिटिकल पार्टियों को दिया है वह उनके एकाउंट में जाता है और उनके एकाउंट

के जरिए से बता सकते हैं कि किस पार्टी को कितना रुपया दिया गया। वह हिसाब मांगना चाहें तो हम दे सकते हैं।

श्री क० ना० तिवारी : क्या सरकार बतायेगी कि इस स्टेप से सुगर की शार्टेज कम हुई और कम्प्रीटीशन में जो फेक्ट्रीज गुड़ और खांडसारी से कम्पीट नहीं कर पाती थी, वह कम्पीट कर सकें इसके लिए यह पालिसी लायी गई तो अगले साल इसका क्या खंजाम होगा, क्या सरकार के सामने इसका कोई एस्टीमेट है ?

श्री कृष्णचंद्रिनी अली अहमद : इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

SHRI HEM BARUA : May I know whether it is not a fact that the companies making contributions to political parties make such contributions out of the black money that they earn and, therefore, it is not shown in their *khaatas* ?

SHRI F. A. AHMED : So far as the contribution given by companies to the political parties is concerned, what they are giving outside the company accounts is not known to me.

श्री सरजू पांडेय : श्रीमाननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि इसके लिए विचार हो रहा है कि किस तरह से कंपनियों पर रोक लगायी जाय ताकि हिन्दुस्तान के जनजीवन को पैसा दे कर के खराब न करें। अभी पिछले दिनों समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ था कि सीमेंट का जो डी-कंट्रोल हुआ था उस जमाने में उससे भी जो रुपया भ्रामा वह कुछ दलों को खास तौर से कॉलिंग पार्टी को दिया गया . . . (व्यवधान) . . . हां, हां स्वतंत्र पार्टी को भी मिला है, जनसंघ को मिला है और श्रीमान् जी को भी, कांग्रेस को भी मिला है। वो माननीय मंत्री जी जब तक ऐसा कानून न बने तब तक कोई ऐसी पाबन्दी उन पर लगाने की बात सोच रहे हैं जिससे इस तरह से पैसा दे कर के सरकारी नीतियों को प्रभावित न किया जा सके ?

श्री कृष्णरहीन अली महमूद : आपने तो दूसरा सबाल उठाया है। जो रुपया एक्सपेंसन के लिए था वह पोलिटिकल पार्टीज को दिया गया। यह मामला गवर्नमेंट के जेरे गौर है कि क्या किया जा सकता है। वह हम सोच रहे हैं। लेकिन जब तक रूल न बदला जाय तब तक पोलिटिकल पार्टीज को रुपया कंपनियां दे सकती हैं। जल्दी उस रूल को बदलें यह हम कोशिश कर रहे हैं।

SHRI AMRIT NAHATA : CACO is not a company. It is a breach of contract; it is a violation of the contract.

SHRI V. KRISHNAMOORTHY : A Bill to ban companies and partnerships and registered companies from giving funds to political parties will not check the giving of black money to the political parties. May I know whether Government propose to check the receipt of black money from companies at the receiving end at least ?

MR. SPEAKER : The receiving end will take both black and white !

SHRI V. KRISHNAMOORTHY : I want to know what Government are contemplating to do to check the receipt of black money at the receiving end.

SHRI S. S. KOTHARI : The hon. Member should suggest a solution.

SHRI F. A. AHMED : The other day I did place before this House my own view that merely stopping all these political contributions by companies to the different political parties will not stop the evil on account of which this objection has been placed before this House. It is for all the political parties together to come to the view that they will not take any money from these companies.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Is he ready to take the initiative ? आप कहिए तो कि आप तैयार हैं ?

SHRI F. A. AHMED : The other day I said that we should not spend so much money at the time of elections, and if the parties while examining the expenditure in elections could reduce thereby show the way, then it can stop this evil of political contributions by private companies.

SHRI HIMATSINGKA : Will the proposed Bill contain provisions for prohibiting the inflow of foreign funds for election purposes ?

SHRI F. A. AHMED : There is no provision in the proposed Bill for inflow of funds from outside.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : Is it not a fact that this question arose as long ago as 1957 when huge funds were collected from joint-stock companies? Subsequently two more general elections have been held. Is it not also a fact that this matter went before the High Court at Bombay and the High Court at Calcutta and both the courts gave judgments that it was undesirable that there was no law preventing such contributions? Instead of amending the company law to prevent it, Government amended the company law by introducing a permissive provision allowing such political contributions? After all these things have happened, the hon. Minister of State says that Government are contemplating legislation, but the hon. Minister himself rises and says that no legislation will help in putting a stop to this. Therefore, may we know what the actual view of Government is, whether they really wish to ban these contributions to political parties by joint-stock companies or whether they are going to leave it as it is in the hope that there will be conventions ?

SHRI F. A. AHMED : I have already said that Government are committed to bringing forward an amendment which will prevent these joint-stock companies from contributing to political parties.

श्री ओ० प्र० त्यागी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि प्राइवेट कंवरन अपने यहां फर्स्ट क्लास आफिसर्स और मिनिस्टर्स के लड़कों और संबंधियों को नौकरी देते हैं और योग्यता से कई गुना अधिक उनको वेतन दे कर रिपबत के रूप में पैसा बेटे हैं और इस प्रकार वह गवर्नमेंट की पालिसीज को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं ? तो इस प्रकार के प्रथाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय सोचा है ?

श्री कृष्णरत्न अली अहमद : यह सवाल पहले भी आ चुका है और कई दफा इसका जवाब दिया जा चुका है। मिनिस्टर होने की हैसियत से कोई कम्पनी उनके लड़के को नौकरी नहीं देती है।

श्री हुकम चन्द कछबाय : देती है, मिनिस्टर होने की वजह से ही देती है।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I can quote the names of the Ministers and their sons who are worthless.

SHRI V. KRISHNAMOORTHY : How many Ministers have given correct statement of expenditure during the last election? All false statements.

श्री कंवर लाल गुप्त : 11 मिनिस्ट्रों के लड़कों को विरला-टाटा के यहां नौकरी मिली है।

श्री कृष्णरत्न अली अहमद : कम से कम मैं यह कह सकता हूँ कि मेरा कोई बच्चा या मेरे किसी रिश्तेदार या दोस्त का बच्चा किसी कम्पनी में नौकर नहीं है।

श्री रवि राय : हाथी साहब का तो है।

श्री कृष्णरत्न अली अहमद : मैं यह भी कह सकता हूँ—जहां तक मेरे इल्म में है—मेरे किसी साथी के बच्चे को इसलिये नौकरी नहीं दी गई है कि वह मिनिस्टर का लड़का है। अगर उसमें कोई काबिलियत है, हुनर है और उसकी बिना पर वह किसी कम्पनी में नौकरी करता है, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें एतराज क्यों है।

श्री ओ० प्र० त्यागी : मैंने यह पूछा कि उनकी योग्यता से कई गुना अधिक वेतन दिया जाता है—क्या ऐसी कोई जानकारी आपको है ?

SHRI D. C. SHARMA : I welcome the assurance given by the Minister that he will bring forward legislation in which those donations to political parties from joint stock companies will be banned, but may I ask the hon. Minister whether in that piece of legislation there will also be a clause that

that political party will be banned, whether it is of an all-India nature or of a provincial nature, which receives donations from joint stock companies in secret, which are not shown either in the account books of the joint stock company or in the accounts books of the party ?

SHRI F. A. AHMED : I do not know how that provision can be brought in here.

MR. SPEAKER : When the Bill comes, he can suggest.

श्री श्री चन्द गोयल : अध्यक्ष महोदय, जब भी यह प्रश्न आता है कि कम्पनीज राजनीतिक दलों को पैसा देती हैं, तो कहा जाता है कि सब दलों को देती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले आम चुनावों में कांग्रेस को और बाकी दलों को किस अनुपात से पैसा दिया गया ? दूसरे—क्या सरकार रिप्रेजेंटेशन आफ़ पियुपिल्ज़ एक्ट में कोई संशोधन कर के इस बात पर रोक लगाना चाहती है या लगाने का इरादा रखती है कि जिस प्रकार चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिये एक मर्यादा है, उसी मर्यादा के अन्दर खर्च कर सकते हैं। उसी तरह से राजनीतिक दलों के लिये भी कोई पाबन्दी होगी कि लोक सभा या विधान सभा की सीटों के लिये कोई भी राजनीतिक दल एक विशेष धनराशि से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा ? क्या इस प्रकार की पाबन्दी लगाने का कोई विचार सरकार कर रही है ?

SHRI RAGHUNATH REDDI : The partywise abstract of political contributions by various companies would be as follows : The Congress : Rs. 24,66,150.17....(Interruptions)

MR. SPEAKER : No, please. You must only take the answer.

SHRI V. KRISHNAMOORTHY : Instead of Rs. 24 crores, he is saying Rs. 24 lakhs.

SHRI RAGHUNATH REDDI : These figures have been compiled out of the balance-sheets received by the Registrars at various points in the country, and these are the figures which we have got at our disposal. Congress : Rs. 24,66,150.17. Swatantra Party: Rs. 4,60,074.3; Jan Sangh: Rs. 33,659; INTUC: Rs. 1,000; Communist

Party, Rs. 2,336; Shiromani Akali Dal, Rs. 550; PSP, Rs. 723; Congress Seva Dal, Rs. 25; Kerala United Front Election Committee, Rs. 350; RSP, Rs. 2,500; Krishak Praja Party, Rs. 200; Akali (Sant), Rs. 150; Akali Party, Rs. 200; SSP, Rs. 5,261; Nagar Socialist Party, Rs. 2,000; Individuals, Rs. 32,400; others, Rs. 32. The total is Rs. 30,07,575.20.

श्री रामावतार शास्त्री : हमारे बिहार में बिहार कांग्रेस कमेटी टाटा-बिरलाओं से बहुत पैसा लिया करती है। मैं जानना चाहता हूँ कि टाटा, बिरला, डालमिया और दूसरी कम्पनियों से बिहार कांग्रेस कमेटी को पिछले चुनाव में या उससे पहले कितने रुपये मिले ?

श्री ओंकारलाल बेरबा : सवाई माधोपुर में शान्तिलाल शाह से कितना मिला ?

MR. SPEAKER : Let him answer again, before anybody else can be called.

SHRI RAGHUNATH REDDI : We have not the figures given by the Registrar of Companies; it is very difficult to identify which is Tata, Birla or any other party. (Interruption)

MR. SPEAKER : I do not know : the figures may be correct or may not be correct. What they have, they have given. But every party knows that the other party has got more. That is the thing. I wonder how it is going to solve the problems now. We would be wasting another 10 minutes.

श्री शिबनारायण : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो फिगर्स बताई हैं, उनसे यह सिद्ध हो गया है कि हमारे मुल्क से हम ने और दूसरे लोगों ने पैसा लिया है। लेकिन जिनको मुल्क से कम पैसा मिला है, उन्होंने विदेशों से पैसा लिया है—मैं जानना चाहता हूँ कि आप विदेशों से आने वाले पैसे के सम्बन्ध में क्या प्रतिबन्ध लगायेंगे ?

MR. SPEAKER : It has already been answered. Next question.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS

*846. SHRI DHIRESWAR KALITA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the United States Agency for

International Development has prepared an Operational workplan to boost India's foreign exchange earnings in the next four years;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) whether Government have approved the plan ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

Main Features of the Operational Work Plan.

The operational Work Plan (OWP), prepared by the US AID Export Promotion Division, describes the various activities/projects contemplated for implementation during the next four years in order to step up India's export earnings. The Plan does not commit either Government until after required administrative and financial clearance have been given by the appropriate authorities.

2. The following activities are proposed to be undertaken under the OWP :

A. Commodity Surveys

The Government of India would undertake, through the US AID Export Promotion Division, the following Commodity Surveys of India's leading export products, both in India and abroad, for identifying specific problem areas and suggesting proposals for remedial action flowing from these proposed surveys :—

- (i) Textile and Made-Up-Garments
- (ii) Machine Tools
- (iii) Leather and Leather Products
- (iv) Marine Products
- (v) Spices
- (vi) Ferro-Manganese
- (vii) Fresh and Processed Fruits and Vegetables
- (viii) Oilcakes and Allied Products.

The US AID would, in consultation with the Government of India, entrust each of these surveys to an appropriate Indian